अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी कंपनी की 52वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। कोविड–19 महामारी के चलते चुनौतियों के बावजूद मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सभी क्षेत्रों में प्रभावी कार्य–निष्पादन किया है।

इस महामारी से मानव व्यवहार और कारपोरेट प्रबंधन में बदलाव आया है। भविष्य उनका है, जो निर्बाध संचार में सफल होंगे साथ ही वर्टिकल हाइरार्की में कमी ला सकते हैं और जिनके पास कारोबारी आसूचना की दृष्टि से मजबूत तंत्र हो। आपकी कंपनी भविष्य के लिए तैयार संगठन बनने की दिशा में अग्रसर है।

ऊर्जा क्षेत्र में, हमने ऐसा परिवर्तन देखा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। विद्युत की मांग बढ़ रही है, आर्थिक क्रियाकलाप फिर से शुरू हो रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण में वृद्धि हो रही है। हरित ऊर्जा में स्पष्ट बदलाव हो रहा है। सरकार इस क्षेत्र को आधुनिक, दक्ष और संधारणीय बनाने के लिए विभिन्न सुधारों का कार्यान्वयन कर रही है। विद्युत क्षेत्र में ये पहल किए जाने से उपभोक्ता का अनुभव बढ़ने और साथ ही समग्र जीवन स्तर बढ़ने की संभावना है।

आपकी कंपनी 1969 में अपनी शुरूआत से ही 'ग्रामीण विद्युतीकरण' में तब से अग्रणी रही है, जब से इसने हरित क्रान्ति में सहायता के लिए सिंचाई पंप सेट हेतु विद्युत प्रदान की। पांच दशकों के बाद, आपकी कंपनी की वित्त व्यवस्था से भारत में हर चौथा बल्ब जलता है। विद्युत क्षेत्र की निरंतर सेवा करते रहने के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, आपकी कंपनी सरकार के सुधार एजेंडा के लिए सहायता करने के प्रति वचनबद्ध है।

आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी कोविड–19 के चलते आई बाधा का सामना कर रही है। अधिकांश आर्थिक क्रियाकलापों पर व्यक्तिगत चर्चाओं की कमी, आर्थिक परिदृश्य की अनिश्चितता, कम निवेश, शिक्षा प्रदान करने के तरीकों में बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा पर्यटन में मंदी से प्रभाव पड़ा है। व्यापार और उद्योग को अपनी महामारी से पूर्व के स्तर तक आने में कुछ समय लगेगा।

संयुक्त राष्ट्र महत्वपूर्ण राजकोषीय और वित्तीय नीतियां बनाकर आर्थिक आपदा से बचने में समर्थ था। दूसरी ओर चीन में विनिर्माण और निर्यातों के जरिए तेजी से लेकिन असमान पुनरुत्थान देखा गया। बाजार के उभरने और विकासशील अर्थव्यवस्था की संभावना 2021 के लिए तो सामान्यतः गिरावट में रही है। परिणामस्वरूप, वैश्विक अर्थव्यवस्था की पुनः प्राप्ति व्यापक टीकाकरण और सतर्कता बरतते हुए आगे बढ़ने पर निर्भर करेगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था भी सरकार द्वारा किए गए व्यापक नीतिपरक हस्तक्षेपों की सहायता से कोविड के झटके से धीरे–धीरे पटरी पर आ रही है। महामारी की शुरूआत से ही, आरबीआई ने आवधिक ऋण की किश्तों पर मोरेटोरियम, कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर ब्याज को टालने, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण में आसानी, संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए समाधान की समय–सीमा में विस्तार और ऋण संस्थानों द्वारा मोरेटोरियम को छोड़कर परिसंपत्ति वर्गीकरण पर रोक सहित अनेक उपाय शुरू किए हैं। सरकार द्वारा प्रदान किए गए इन उपायों और कई अन्य राहतों के कारण, अर्थव्यवस्था पर दबाव कम करने में सहायता मिली है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुमानों के अनुसार, भारत वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 9.5% के विकास के पूर्वानुमान के साथ, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ रही प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरकर सामना आया है। आईएमएफ को भी वित्तीय वर्ष 2022–23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8.5% तक की वृद्धि होने की आशा है। आर्थिक पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले कारकों में, विवेकसम्मत व्यय जारी रखने के अलावा कोविड–19 की सफलतापूर्वक रोकथाम शामिल है।

विद्युत क्षेत्र परिदृश्य

चूंकि विद्युत आवश्यक सेवाओं के तहत आती है, अतः विद्युत की खपत पर कोविड–19 का प्रभाव सीमित था। अभी भी इस क्षेत्र के समक्ष विलंबित परियोजना निष्पादन समय–सीमा, वित्त व्यवस्था पर दबाव और लिक्विडिटी की समस्या जैसे मुद्दे हैं। यह क्षेत्र सरकार से सशक्त नीतिगत सहायता और सेक्टरल सुधारों के साथ इन चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है।

मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, भारत में विद्युत स्टेशनों की कुल संस्थापित क्षमता 382 गीगावाट है। धीरे–धीरे परंपरागत विद्युत स्रोतों से ध्यान हटाकर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ लगाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में उच्चतर स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप देखे जा सकते हैं, जिससे विद्युत की मांग बढ़ेगी। साथ ही, महामारी के कारण अनिश्चितता और अन्य क्षेत्रों तक आवागमन में प्रतिबंधों के कारण विद्युत की मांग बढ़ सकती है।

विगत कुछ वर्षों में, पारेषण क्षेत्र में एक अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है, जिसमें देश के ग्रिड विस्तार लक्ष्यों को हासिल करने में निजी भागीदारों की एक अहम भूमिका रही है। केंद्र और राज्य स्तर पर पारेषण यूटिलिटियों द्वारा नई प्रौद्योगिकियों में काफी निवेश किए जाने की संभावना है ताकि ग्रिड को और अधिक विश्वसनीय, अनुकूल, सुरक्षित और स्मार्ट बनाया जा सके।

वितरण क्षेत्र में विगत कुछेक वर्षों में कई सुधार सामने आए हैं, जो कि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और दक्षता लाने पर केंद्रित हैं। भारत ने पहले से ही संघ–राज्य क्षेत्रों में अपनी विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे अधिक प्रतिस्पर्धा आएगी, जिसके कारण डिस्कॉमों पर अपने कार्य–निष्पादन स्तर को सुधारने और एक अधिक उपभोक्ता–केंद्रित संकल्पना अपनाने के लिए दबाव डाला जा सकेगा।

मई, 2020 में, केंद्र सरकार ने महामारी की पृष्ठभूमि में, आत्मनिर्भर भारत के तहत डिस्कॉमों के लिए एक लिक्विडिटी निषेचन योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, आरईसी और पीएफसी ने डिस्कॉमों के लिए, राज्य सरकारों से विद्युत की बकाया राशि और वितरित न की गई सब्सिडी के रूप में प्राप्त होने वाली राशि के एवज में रियायती दरों पर विशेष दीर्घावधिक ट्रांजिशनल ऋण प्रदान किए हैं, ताकि वे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, उत्पादन और पारेषण कंपनियों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों पर बकाया अपनी राशि का भुगतान कर सकें।

फ्लैगशिप सरकारी कार्यक्रम

आपकी कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 2014 में ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलुओं, देश में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित परियोजना घटकों के माध्यम से 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' सुविधा प्रदान करना शामिल करते हुए, शुरू की गई एक फ्लैगशिप योजना, *दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना* अर्थात डीडीयूजीजेवाई के लिए एक नोडल एजेंसी है। आपकी कंपनी सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में शुरू की गई सौभाग्य योजना अर्थात *प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना* के प्रचालनीकरण के लिए भी नोडल एजेंसी है।

यह उल्लेखनीय है कि देश में सभी आवासित जनगणना गांव 28 अप्रैल, 2018 को विद्युतीकृत हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत दिनांक 31 मार्च, 2021 तक 2.82 करोड़ से अधिक घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

हाल ही में, आपकी कंपनी ने सभी डिस्कॉमों के लिए विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम के तहत प्रमुख विनियामक मानदंडों पर एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में प्रमुख विनियामक मानदंडों का संकलन बैंचमार्क और तुलनात्मक आकलन प्रदान किया गया है, जिनमें इस बात पर व्यापक विचार किया गया है कि कैसे संबंधित विद्युत वितरण यूटिलिटी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने की जरूरत है।

विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में, आपकी कंपनी ने 'डिस्कॉम उपभोक्ता सेवा सूचकांक' के लिए एक फ्रेमवर्क भी विकसित किया है, जिसमें डिस्कॉमों को अपने उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं जैसे विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति, कनेक्शन और अन्य सेवाएं, मीटर बिल सेवा और दोष निवारण के आधार पर रेटिंग दी जाती है। इस रेटिंग का उद्देश्य डिस्कॉमों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है ताकि उन्हें संगत क्षेत्रों में अपने कार्य–निष्पादन को सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

आपकी कंपनी वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक की पांच वर्षों की अवधि के दौरान भारत सरकार से 97,631 करोड़ रूपए की सकल बजटीय सहायता और 3,03,758 करोड़ रूपए के परिव्यय से एक सुधार–आधारित तथा परिणाम–संबद्ध योजना, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के लिए नोडल एजेंसियों में भी शामिल है। इस योजना के तहत वित्तीय सुधारों से जुड़े सहमत मूल्यांकन फ्रेमवर्क के आधार पर मूल्यांकित डिस्कॉम द्वारा पूर्व–अर्हता मानदंडों और आधारभूत न्यूनतम बैंचमार्कों की उपलब्धि के आधार पर आपूर्ति अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए सशर्त वित्तीय सहायता प्रदान करके, निजी क्षेत्र के डिस्कॉमों को छोड़कर, सभी डिस्कॉमों/विद्युत विभागों की प्रचालनात्मक दक्षताओं और वित्तीय संधारणीयता में सुधार की अपेक्षा की गई है। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024–25 तक एटीएंडसी हानियों को अखिल भारतीय स्तर पर कम करके 12–15% तक लाना और एसीएस–एआरआर के अंतर को शून्य पर लाना है।

नीति संबंधी पहल

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी ने नई नीतियां और दिशानिर्देश शुरू करके तथा मौजूदा नीतियों और दिशानिर्देशों में संशोधन करके अपने नीतिपरक कार्यढांचे को सुदृढ़ करना जारी रखा। इसमें कोविड–19 के तहत अदायगी समय–सीमा को बदलकर मूल किश्तों और/अथवा ब्याज को आस्थगित करने की नीति, कोविड–19 के तहत डिस्कॉमों को विशेष दीर्घावधिक ट्रांजिशन ऋण योजना, उदय योजना की सीमाओं के भीतर डिस्कॉमों को विशेष ऋण की योजना और उदय योजना की सीमाओं में छूट देकर डिस्कॉमों को विशेष ट्रांजिशन ऋण की योजना शामिल है।

कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में अपनी नीतियां शुरू की हैं और उनकी समीक्षा की है जिनमें वचनबद्धता–पत्र के लिए नीति, राज्य विद्युत यूटिलिटियों की ग्रेडिंग के संबंध में नवीकरणीय ऊर्जा दिशानिर्देशों में आशोधन, परियोजना मूल्यांकन और एंटिटि मूल्यांकन दिशानिर्देशों में संशोधन तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पुनर्वित्तपोषण नीति में आशोधन शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने अपनी ब्याज दर संरचना में भी समान रूप से कटौती की है ताकि बाजार की दरों के अनुसार चल सकें और क्षेत्र की समग्र लाभप्रदता के लिए योगदान दिया जा सके।

प्रचालनात्मक निष्पादन

समग्र विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में सेवा करने वाले एक वित्तीय संस्थान के रूप में, आपकी कंपनी के प्रमुख उत्पादों में सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों के ऋणकर्ताओं के लिए रुपे आवधिक ऋण और अन्य ऋण शामिल हैं, जो पारंपरिक ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, पारेषण और वितरण तथा विद्युत परियोजनाओं के साथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज वाले क्रियाकलाप के क्षेत्रों में हैं। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी अथवा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने विभिन्न विद्युत क्षेत्र परियोजनाओं/योजनाओं के लिए 1,54,820.87 करोड़ रूपए की कुल ऋण सहायता स्वीकृत की है। इसमें उत्पादन परियोजनाओं के लिए 39,613.53 करोड़ रूपए, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 17,171.34 करोड़ रूपए, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 19,492.75 करोड़ रूपए, आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत सरकार की लिक्विडिटी निषेचन योजना के लिए 60,191.36 करोड़ रूपए और अल्पावधिक व मध्यावधिक ऋणों सहित अन्य ऋणों के लिए 4,750.00 करोड़ रूपए शामिल हैं। इसके अलावा, ₹13,601.89 करोड़ की बकाया राशि, जिस पर आरबीआई के निर्देशों और बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिस्थगन नीति के अनुसार स्थगन बढ़ाया गया था, को भी उपरोक्त संस्वीकृतियों में शामिल किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी ने 92,987.49 करोड़ रूपए की कुल धनराशि वितरित की है, जिसमें उत्पादन परियोजनाओं के लिए 25,929.76 करोड़ रूपए, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 3,265.13 करोड़ रूपए, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 19,301.22 करोड़ रूपए, आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत सरकार की लिक्विडिटी निषेचन योजना के लिए 39,115.50 करोड़ रूपए और अल्पावधिक व मध्यावधिक ऋणों सहित अन्य ऋणों के लिए 3,900.79 करोड़ रूपए शामिल हैं, जो कि भारत सरकार की डीडीयूजीजेवाई, डीडीयूजीजेवाई–डीडीजी और सौभाग्य योजनाओं के तहत 1,475.09 करोड़ रूपए के काउंटर–वित्तपोषण के अतिरिक्त है। उपरोक्त के अलावा, आपकी कंपनी ने भारत सरकार से 4,940.62 करोड़ रूपए की कुल सब्सिडी अर्थात डीडीयूजीजेवाई के तहत 4,527.01 करोड़ रूपए, डीडीयूजीजेवाई–डीडीजी के तहत 25.49 करोड़ रूपए और सौभाग्य योजना के तहत 388.12 करोड़ रूपए, भी संवितरित की है।

वित्तीय निष्पादन

आपकी कंपनी ने सभी मुख्य निष्पादन संकेतकों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान काफी अच्छा कार्य–निष्पादन किया है। कोविड–19 के बावजूद, आपकी कंपनी ने सशक्त ऋण प्रोफाइल के कारण और ऋणों के विविध स्रोतों तक पहुंच के लिए, अपनी लिक्विडिटी की स्थिति

पर किसी महत्वपूर्ण प्रभाव का सामना नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी के पास उच्च गुणवत्ता लिक्विड परिसंपत्तियों के अलावा, कार्यशील पूंजी के रूप में और विभिन्न बैंकों से आवधिक ऋण सीमाओं के रूप में, पर्याप्त लिक्विडिटी बफर है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी की कुल प्रचालनात्मक आय विगत वित्तीय वर्ष के दौरान 29,765.21 करोड़ रूपए की तुलना में 35,387.89 करोड़ रूपए थी। कर पश्चात लाभ और कुल व्यापक आय विगत वित्तीय वर्ष में 4,886.16 करोड़ रूपए और 4,336.37 करोड़ रूपए की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए क्रमशः ₹8,361.78 करोड़ और ₹8,818.30 करोड़ थी। प्रति शेयर आय भी 42.34 रूपए के उच्च स्तर दर्ज की गई थी और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर बुक वैल्यू 219.89 रूपए तक पहुँच गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की सकल ऋण परिसंपत्ति बुक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 3,22,424.68 करोड़ रूपए की तुलना में 3,77,418.15 करोड़ रूपए थी, जो 17% की वृद्धि है। कंपनी के निवल मूल्य में भी 24% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 35,076.56 करोड़ रूपए की तुलना में 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 43,426.37 करोड़ रूपए तक पहुँच गई है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात 19.72% था, जिसमें भावी वृद्धि में सहायता के लिए कंपनी की क्षमता शामिल है।

आपकी कंपनी की घरेलू ऋण दस्तावेज की "एएए" रेटिंग जारी रही, जो कि क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग और अनुसंधान एवं आईसीआरए–क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सर्वाधिक रेटिंग है। आपकी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों मूडीज और फिच से भी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग के रूप में क्रमशः "बीएए3" और "बीबीबी–" रेटिंग मिली है।

आपकी कंपनी की क्रेडिट इम्पेयर्ड एसेट (स्टेज–III) न्यून स्तरों पर जारी रही। दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, सकल क्रेडिट इम्पेयर्ड एसेट (स्टेज–III) सकल ऋण परिसंपत्तियों का 4.84% और निवल क्रेडिट इम्पेयर्ड एसेट (स्टेज–III) ऋण परिसंपत्तियों का 1.71% थी। आपकी कंपनी ने संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के पहलुओं को देखने के लिए ऐसी परियोजनाओं में आई समस्याओं और उपयुक्त माध्यमों से प्रत्येक मामले के निपटान के लिए एक समर्पित टीम तैयार की है।

पूंजीगत संरचना

दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रूपए थी, जिसमें 10 रूपए प्रत्येक के 500 करोड़ रूपए की इक्विटी शेयर शामिल हैं। कंपनी की जारी की गई और प्रदत्त शेयर पूंजी 1,974.92 करोड़ रूपए थी, जिसमें 10 रूपए प्रत्येक के 197,49,18,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। भारत सरकार का उद्यम, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के पास आपकी कंपनी में 52.63% इक्विटी हिस्सा है और शेष शेयर जनता द्वारा धारित हैं।

लाभांश

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 6 रूपए प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश और 10 रूपए प्रत्येक के 5 रूपए प्रति इक्विटी शेयर का दूसरा अंतरिम लाभांश घोषित किया था, जिसका भुगतान क्रमशः दिसंबर, 2020 और मार्च, 2021 में किया गया है।

इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने 10 रूपए प्रत्येक के 1.71 रूपए प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की भी सिफारिश की है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। यदि अनुमोदन कर दिया जाता है, तो वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कुल लाभांश 10 रूपए प्रत्येक के 12.71 रूपए प्रति इक्विटी शेयर की राशि होगी, जिसमें कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 127.10% शामिल है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए 110% के लाभांश से अधिक है।

गुरूग्राम में नया कार्यालय भवन

आपकी कंपनी ने हाल ही में गुरूग्राम, हरियाणा में अपने नए कार्यालय से काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें कंपनी का कारपोरेट कार्यालय स्थित है। यह एक विशिष्ट भवन है, जिसमें रूफटॉप पर 964 किलोवाट पीक सौर पीवी संयंत्र है। भवन में कई अत्याधुनिक विशेषताएं हैं, जैसे उचित फिनिश के साथ सफेद कंक्रीट सरफेस, उठी हुई फ्लोरिंग, एयर कंडीशनिंग की विद्युत खपत में कमी लाने के लिए स्लैब हेतु रेडियंट कूलिंग, एकीकृत भवन प्रबंधन प्रणाली, ऑटोमेटेड सेंसर नियंत्रित लाइटिंग और मोटरयुक्त ब्लाइंड सहित बायो–क्लाइमेटिक ग्लास फेकेड, जो कि एक भावी तैयार संगठन के लिए काफी अनुकूल है।

मानव संसाधन प्रबंधन

महामारी के कारण, कर्मचारियों के हित पर विगत वर्ष में काफी ध्यान दिया गया था। कर्मचारी को कोविड प्रोटोकोल का पालन करते हुए उत्पादकता के उच्च स्तरों पर कार्य करने के लिए प्रेरित और समर्पित थे। प्रशिक्षण और वेबिनार नियमित रूप से चलाए गए थे, जो कि न केवल उनके कौशल–सेट को सुधारने के लिए थे, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने के लिए तैयार करने हेतु भी थे। विश्वास और सहयोग का वातावरण निर्मित करने के लिए नियमित पारस्परिक चर्चाएं की गई थीं।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रों से 9 कार्यपालकों की नियुक्ति की। दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 428 थी। कंपनी ने संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी स्तरों पर प्रभावी मानव संसाधनों की तैनाती पर बल दिया है।

जोखिम प्रबंधन कार्यढांचा

आपकी कंपनी की एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें क्रेडिट जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और बाजार जोखिम शामिल हैं। ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए प्रणालीबद्ध जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं।

कंपनी क्रेडिट–जोखिम को कम करने के लिए विस्तृत प्रणाली के साथ संरचित मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाती है। प्रचालनात्मक जोखिमों का प्रबंधन एक व्यापक जोखिम रजिस्टर के जरिए किया जाता है, जिसमें सभी कार्यात्मक क्षेत्र शामिल हैं। लिक्विडिटी जोखिम को करने के लिए, अनुमानित वितरणों और परिपक्व बाध्यताओं के आधार पर भावी संसाधन जुटाने सहित मिश्रित रणनीतियां हैं। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने बाजार जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न जोखिम सीमाओं को कार्यान्वित किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी पहलें

आपकी कंपनी विभिन्न आईटी पहलों के जरिए अपनी कारोबारी प्रक्रियाओं का निरंतर डिजिटलीकरण कर रहा है। आपकी कंपनी ई–ऑफिस के कार्यान्वयन के साथ पेपरलेस बनने वाला भारतीय विद्युत क्षेत्र का पहला सीपीएसई था, जिसमें ई–ऑफिस को अपग्रेड करके एनआईसी ई–ऑफिस किया गया है। आपकी कंपनी ने अपने ई–बिजनेस ईआरपी को नवीनतम वर्जन के साथ संशोधित किया है; और ईआरपी हार्डवेयर को आपकी कंपनी के डाटासेंटर को में प्राइवेट क्लाउड एनवायरमेंट में बदला है।

कंपनी के नेटवर्क और सुरक्षा उपकरणों को नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ अपग्रेड किया गया है। एक सुरक्षित वीपीएन नेटवर्क सुदूर स्थानों से आपकी आरईसी नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए प्रयोक्ताओं को सुविधा प्रदान करता है, जिससे निर्बाध प्रचालन सुविधा मिली है। आपकी कंपनी डाटा सेंटर और आपदा रिकवरी केंद्र पर डाटा लीकेज को रोकने के लिए एक प्रणाली भी कार्यान्वित करता है ताकि गोपनीय और महत्वपूर्ण सूचना कारपोरेट नेटवर्क से बाहर साझा न हो।

आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग

आपकी कंपनी का हैदराबाद में एक प्रमुख विद्युत क्षेत्र प्रशिक्षण संस्थान नामतः आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमएटी) है। आरईसीआईपीएमएटी की स्थापना 1979 में हुई थी, जो कि विभिन्न विद्युत क्षेत्र के संगठनों के इंजीनियरों और प्रबंधकों की प्रशिक्षण और विकास आवश्यकताओं को पूरा करता है। आरईसीआईपीएमएटी अंतर्राष्ट्रीय कार्यपालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार का एक भागीदार संस्थान भी है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आरईसीआईपीएमएटी ने 1250 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें आरईसी के कार्यपालकों के लिए डीडीयूजीजेवाई के तहत विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, विद्युत सुरक्षा, विद्युत यूटिलिटियों की संधारणीयता, सुरक्षा पहलुओं और ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली तथा रूफटॉप सौर प्रणालियों जैसे आरईसी प्रायोजित कार्यक्रम, ओपन कैलेंडर कार्यक्रम और इन–हाउस प्रशिक्षण सत्र शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में 28,678 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया था, जिसमें कुल मिलाकर 82,420 मानव दिवसों की उपलब्धि शामिल है।

सीएसआर और संधारणीय विकास

आपकी कंपनी की सीएसआर निधियां सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसायटी "आरईसी फाउंडेशन" के जरिए संचालित होती हैं। समस्त सीएसआर पहलें सामाजिक लाभ की परियोजनाओं पर संकेंद्रित हैं ताकि व्यापक रूप में लाभार्थियों तक पहुँच सकें। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आरईसी के सीएसआर क्रियाकलाप सफाई और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देख–रेख के संवर्धन, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरणीय संधारणीयता और ग्रामीण अवसंरचना विकास के क्षेत्रों में किये गये थे। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने विभिन्न आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और कुपोषण में कमी लाने के लिए भी योगदान दिया है।

आपकी कंपनी में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बने नियमों के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार एक सुपरिभाषित "कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता नीति" है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के लिए कुल 147.77 करोड़ रूपए की धनराशि खर्च की है, जिसमें पीएम केयर्स फंड के लिए 50 करोड़ रूपए, प्रवासी कामगारों, स्वास्थ्य कर्मियों और वंचित लोगों के लिए खाना, राशन, सेनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट इत्यादि प्रदान करने के लिए 6.93 करोड़ रूपए तथा कोविड–19 टीकों को स्टोर करने के लिए कोल्ड चेन उपकरण प्रदान करने हेतु 0.72 करोड़ रूपए शामिल हैं।

निगमित सुशासन

आपकी कंपनी, निगमित सुशासन में श्रेष्ठ परिपाटियों को अपनाने और उनका अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी अपने क्षेत्राधिकार में, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश, 2010 और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालयी मानकों के तहत लागू सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है। कंपनी नियोक्ता प्राधिकारी अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के पास अपने बोर्ड

में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में मामले का अनुसरण भी कर रही है। आशा है कि अपेक्षित संख्या में निदेशकों की शीघ्र ही नियुक्ति होगी।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी को महारत्न और नवरत्न श्रेणी में रनर अप के रूप में इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स से निगमित सुशासन के लिए 10वां पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था।

पुरस्कार और सम्मान

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी ने एक्सचेंज4मीडिया द्वारा वीमेन अचीवर्स अवार्ड 2020 के अवसर पर बेस्ट ऑर्गनाइजेशन फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, स्कॉच अवार्ड फॉर रिस्पांस टू कोविड, महात्मा अवार्ड फॉर सीएसआर एक्सीलेंस 2020, सीएसआर, आईटी, पर्यावरण एवं मानव संसाधन श्रेणियों में नेशनल पीएसयू एक्सीलेंस अवार्ड और महिला सशक्तिकरण के लिए सीएसआर शाइनिंग स्टार अवार्ड सहित विभिन्न अवार्ड और सम्मान प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त, रेपुटेशन टुडे ने आपकी कंपनी की कारपोरेट संचार टीम को भारत में टॉप 30 में मान्यता दी है।

सहायक और संयुक्त उद्यम

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को एक कंपनी के रूप में विलय किया गया था ताकि प्रचालनों में बेहतर प्रगति, विभिन्न बाजार घटकों की बेहतर प्राप्ति और अधिक पूंजी आधार तथा साझा संसाधनों के लाभ प्राप्त हो सकें। विलय की गई कंपनी को अब आरईसी पावर डेवलेपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड *(पूर्ववर्ती नाम आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, "आरईसीपीडीसीएल")* के नाम से जाना जाता है।

आरईसीपीडीसीएल विद्युत क्षेत्र में परियोजना कार्यान्वयन और परामर्शी सेवाओं के कारोबार में लगी है अर्थात वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण कार्यों का कार्यान्वयन, ग्रिड/ऑफ–ग्रिड सौर (पीवी) परियोजनाओं का कार्यान्वयन, स्मार्ट मीटरों की संस्थापना, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना, तृतीय पक्षकार निरीक्षण, प्री–डिस्पैच मैटेरियल निरीक्षण और डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस आदि जैसी राज्य–वित्तपोषित योजनाओं के तहत परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में कार्य करना।

इसके अतिरिक्त, विलयन के अनुसरण में, आरईसीपीडीसीएल समय–समय पर विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्र अंतर–राज्यीय और अंतरा–राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए "बोली प्रक्रिया समन्वयक" के रूप में भी कार्य करती है। प्रत्येक स्वतंत्र अंतर–राज्यीय/अंतरा–राज्यीय पारेषण परियोजना के विकास के लिए, आरईसीपीडीसीएल अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक परियोजना विशिष्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) निगमित करती है, वह भी आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन जाती है। टीबीसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाताओं के चयन के बाद, ऐसी सहायक कंपनियों को सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आरईसीपीडीसीएल ने पिछले वित्तीय वर्ष के ₹222.18 करोड़ की आय की तुलना में ₹184.69 करोड़ की आय दर्ज की। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कर पश्चात लाभ ₹25.62 करोड़ था, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह ₹66.91 करोड़ था। इसके अलावा, 31 मार्च, 2021 को आरईसीपीडीसीएल की निवल संपत्ति ₹297.99 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च, 2020 को यह ₹280.80 करोड़ थी।

आरईसी की संयुक्त उद्यम कंपनी यथा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) है, जिसके साथ तीन अन्य विद्युत क्षेत्र के पीएसयू ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में अग्रणी कार्य कर रहे हैं। ईईएसएल ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों की बाजार पहुँच उत्पन्न करने और बनाए रखने के लिए विशेषकर सार्वजनिक सुविधाओं के क्षेत्र में, जैसे नगरपालिका, भवन, कृषि, उद्योग इत्यादि और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की अनेक योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए बनाई गई है। ईईएसएल जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्रवाई योजना (एनएपीसीसी) के तहत आठ राष्ट्रीय मिशनों में से एक राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) के बाजार से संबंधित क्रियाकलापों की अगुवाई भी कर रही है। आरईसी ने ईईएसएल की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के लिए 218.10 करोड़ रूपए (22.18%) का योगदान किया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ईईएसएल के अनंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर, वर्ष के लिए उसका टर्नओवर 1,471.85 करोड़ रूपए (एकल आधार पर) था। इसके अतिरिक्त, वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमशः 43.96 करोड़ रूपए और 32.87 करोड़ रूपए था।

भावी पथ

यद्यपि कोविड–19 महामारी के चलते कारोबार और उद्योग के लिए अनेक चुनौतियां आई हैं, लेकिन इससे विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए अनेक अवसर भी प्रदान किए गए हैं। डिस्कॉम अवसंरचना अपग्रेड के लिए 3 लाख करोड़ रूपए से अधिक के परिणाम और सुधार संबद्ध वित्तीय पैकेज भविष्य की योजना के लिए है जिससे वितरण क्षेत्र के विकास में सहायता मिलेगी। इस प्रस्ताव से उपभोक्ताओं को अपने विद्युत आपूर्तिकर्ता चुनने का अवसर मिलेगा, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इससे दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी और वितरण क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को

बढ़ाने की सरकार की इच्छा की पूर्ति होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मॉडल के जरिए पारेषण परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण एक प्रशंसनीय प्रयास है, जिससे विद्युत उत्पादन की तीव्र गति के अनुकूल पारेषण क्षमता में वृद्धि करने और मांग में वृद्धि करने में मदद मिलेगी।

नवीकरणीय ऊर्जा और साथ ही हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा तथा स्मार्ट मीटरिंग की ओर परिवर्तन के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई गई हैं। घरेलू विनिर्माण का विस्तार करना नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में सहायता के लिए आवश्यक है। सौर सेलों और पैनलों के लिए चरणबद्ध स्थानीय विनिर्माण योजना से दीर्घावधि में सौर सेलों और मॉड्यूलों के लिए आयातों पर निर्भरता को न्यूनतम करने, आत्मनिर्भर भारत के लिए योगदान देने में मदद मिलेगी। बैट्री विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से देश में भंडारण विनिर्माण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में भी वृद्धि होगी, जिसके नवीकरणीय ऊर्जा और ई–मोबिलिटी क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। साथ ही, संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को न्यूनतम करने के लिए इस क्षेत्र पर ध्यान देना होगा।

यद्यपि निजी क्षेत्र के नवीकरणीय ऊर्जा में निवेशों में अग्रणी बनने की संभावना है, लेकिन परंपरागत और परमाणु ऊर्जा में निवेश अधिकांशतः सार्वजनिक क्षेत्र से आएंगे। आपकी कंपनी विद्युत क्षेत्र में प्रस्तुत वर्तमान और उभरते अवसरों के लिए सुपरिचित है। आरईसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा बहुपक्षीय विकास संगठनों के साथ गहन व्यावसायिक भागीदारी निर्मित कर रही है ताकि कंपनी प्रतिस्पर्धी दरों पर और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों के अनुसार संसाधन जुटाने में सक्षम हो सके।

भविष्य में, आपकी कंपनी न केवल एक वित्तपोषण भागीदार के रूप में बल्कि अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से भी नए उभरते क्षेत्रों में विविधीकरण करने के लिए प्रयासरत है। कुल मिलाकर, आपकी कंपनी एक मजबूत, सुस्थिर और विश्वसनीय विद्युत क्षेत्र बनने के अंतिम उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है।

आभार

मैं, माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, माननीय विद्युत राज्य मंत्री, सचिव (विद्युत) और विद्युत मंत्रालय के अन्य अधिकारियों का, उनके निरंतर समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं, होल्डिंग कंपनी, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं, वित्त मंत्रालय, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, नीति आयोग, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज के अधिकारियों का उनकी सद्भावना एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवालयी लेखापरीक्षकों, रजिस्ट्रार एवं कंपनी से जुड़े अन्य व्यावसायिकों को इनके योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं सभी निवेशकों, उधारदाताओं, उधारकर्ताओं और ग्राहकों तथा राज्य सरकारों, राज्य विद्युत यूटिलिटी और विद्युत क्षेत्र में निजी उद्यमियों को कंपनी में अपना विश्वास बनाए रखने के लिए विशेष धन्यवाद देता हूँ।

अंत में, मैं बोर्ड में अपने साथियों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं, आरईसी के सभी कार्मिकों के अथक प्रयासों के लिए उनकी भी सराहना करता हूँ। यह आप सभी के निरंतर प्रयासों और सहयोग से ही संभव हो पाया है कि आरईसी आज सर्वांगीण विकास के मार्ग पर अग्रसर है। धन्यवाद! जय हिंद!

शुभकामनाओं सहित,

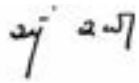

संजय मल्होत्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

27 अगस्त, 2021